





# जालना के खरपूड़ी प्रोजेक्ट में दलालों के आर्थिक हितों को साधने का प्रयास

## अंबादास दानवे का आरोप

विशेष प्रतिनिधि

मुंबई:

जालना जिले के खरपूड़ी में एक नए प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय जनता के तीव्र विरोध के बावजूद, संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कुछ व्यवसायियों और दलालों के आर्थिक हितों को साधने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह गंभीर आरोप विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने लगाया है।

महायुत सरकार ने खरपूड़ी में एक नया प्रोजेक्ट सुरु करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय स्तरों पर कई निर्णय लिए गए हैं। हालांकि, इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

## नशा विरोधी टास्क फोर्स के लिए ३६४ पदों की भर्ती को मंजूरी

मुंबई, १८ फरवरी (विशेष प्रतिनिधि):

राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में नेशे के खिलाफ एक विशेष टास्क फोर्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस टास्क फोर्स के लिए ३६४ नए पदों की भर्ती और अवश्यक बजट को भी स्वीकृति दी गई।

भर्ती प्रक्रिया और पदों का विवरण

३१ अगस्त २०२३ के सरकारी आदेश के अनुसार, कुल ३१० पद नियमित रूप से और ३६ बद्र बाहरी एजेंसियों के माध्यम से भरे जाएंगे।

नियमित पदों में शामिल होंगे:

विशेष पुलिस महानिरीक्षक - १, पुलिस उपमहानिरीक्षक - १, पुलिस अधीक्षक - ३, अपर पुलिस अधीक्षक - ३, पुलिस निरीक्षक - १५, अपर अपर पुलिस निरीक्षक - १५, पुलिस उपनिरीक्षक - २०, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक - ३५, पुलिस उपनिरीक्षक - ४८, पुलिस सिपाही - ८३, चालक हवलदार - १८, कार्यालय अधीक्षक - १, वरिष्ठ लिपिक - ११,

बाहरी एजेंसियों से भरे जाने वाले पद: वैज्ञानिक सहायक - ३, विधि अधिकारी - ३, कार्यालय सहाय्यक - १८, सफाई कर्मचारी - १२,

आवश्यक बजट को भी मंजूरी

नियमित खर्च के तिर १९.२२ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वाहन खरीद और अन्य अनियमित खर्चों के लिए ३.१२ करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

सरकार के इस फैसले से राज्य में नेशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और अपराधों पर अंकश लगाया जा सकेगा।

## म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए १,५१४ करोड़ रुपये मंजूर मंत्रिमंडल का निर्णय

मुंबई, १८ फरवरी (विशेष प्रतिनिधि):

महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजना के तहत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना के लिए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित करने और योजना की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए १,५१४ करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया।

परियोजना से किसानों को होगा

लाभ

इस परियोजना से हर साल करीब ३१८ मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता पूरी होगी। कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन परियोजना के तहत ताकारी और म्हैसाळ दो अलग-अलग सिंचाई योजनाएं शामिल हैं।

परियोजना के तहत:

कृष्णा नदी से २३.४४ अघफू पानी उठाया जाएगा।

यह पानी सांगली जिले के मिरज, कवठे महांकाल, तासगांव, जत और सोलापुर जिले के सांगोला व मंगळवेडा तालुकों में १,०८,१७ हेक्टेयर सूखा प्रभावित भूमि की सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा।

सौर ऊर्जा के उपयोग से परियोजना

है।

२०१८ में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को २०२० में अव्यवहारिक बताया गया था।

इस प्रोजेक्ट की संकल्पना

२०१८ में सिडिको (उखउजर) द्वारा

प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता की जांच

के लिए इस प्रोजेक्ट को साधने

के लिए इस प्रोजेक्ट को आरोप विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने लगाया है।

महायुत सरकार ने खरपूड़ी में एक नया

प्रोजेक्ट सुरु करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न

प्रशासनिक और स्वीकृति स्तरों पर कई निर्णय

लिए गए हैं। हालांकि, इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता को लेकर कई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह गंभीर आरोप विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने लगाया है।

की गई। इसके बाद घञ्चचक्र की नई रिपोर्ट

के आधार पर छिले साल इस प्रोजेक्ट को

अंतिम मंजूरी दी दी गई।

पुराना रिपोर्ट

अव्यवहारिक, नया रिपोर्ट

व्यवहारिक - सरकार पर सवाल

अंबादास दानवे ने सवाल उठाते

हुए कहा, जब २०२० में यह

प्रोजेक्ट अव्यवहारिक था, तो कुछ

वर्षों बाद अव्यवहारिक

कैसे हो गया? उन्होंने आरोप

पुराना रिपोर्ट के बीच का अंतर

पारदर्शी तरीके से स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन

इसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा

है। प्रोजेक्ट से पहले ही कुछ व्यवसायियों

को आरोप लगाया कि, इस प्रोजेक्ट को

यह भी आरोप लगाया कि, इस प्रोजेक्ट को

शुरू करने से पहले ही कुछ व्यवसायियों

को संबंधित विभाग के अधिकारियों

के साथ अव्यवहारिक संबंधों के कारण इसकी पूरी

जानकारी दी गई।

पुराना रिपोर्ट

जानकारी के आधार पर

उन व्यापारियों ने स्थानीय किसानों से

सस्ते दामों पर जमीन खरीद ली। अब जब

सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू कर रही है,

तो उन जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ गई

है। इससे दलालों और बड़े व्यावसायिक

समूहों को अव्यवहारिक लाभ मिलेगा, जबकि

मूल जमीन मालिक और जिसन वर्ग इससे

वर्चित रह जाएगे। प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है, वह पूरी

प्रक्रिया भी संदेहास्पद है। उन्होंने मांग की

कि सरकार को इस पूरे समाले की पारदर्शी

जांच करनी चाहिए।

परली में राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा स्वराज्य सप्ताह का आयोजन

## मंत्री धनंजय मुंडे की संकल्पना के तहत होगा कार्यक्रम

परली वैजनाथ, १८ फरवरी (प्रतिनिधि):

महाराष्ट्र के अन्न, नागरी आपूर्ति

एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय

मुंडे की संकल्पना के

तहत परस्ती वैजनाथ शहर

में इस वर्ष भी हिंदूवी

स्वराज्य के संस्थापक

छवपति शिवाजी महाराज

की जयती का भव्य

आयोजन किया जा रहा

है।

१९ से २७ फरवरी

तक होगा स्वराज्य सप्ताह

का आयोजन

शिवजयंती समारोह १९ फरवरी

को सुबह १० बजे छवपति शिवाजी

महाराज चौक पर

शिवकालीन महाद्वारा की

प्रतिकृति, विशेष

प्रकाश व्यवस्था और

सेल्फी पांडिट तैयार

किया जाएगा।

१९ से २७ फरवरी

तक होगा स्वराज्य सप्ताह

का आयोजन

